in th$_e$ country with the participation of public sector undertakings and non-resident Indians;

(b) what is the equity participation of PSUs and NRIs in the services;

(c) what is Government's assessment about their performance so far as the efficiency of PSUs is concerned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) As per available information, one joint venture company namely Management and Technology Applications (India) Ltd. with equity participation of 51 per cent by an NRI Company namely iManagement and Technologies International Inc. USA and balance 49 per cent contributed equally by six Indian Public Sector Undertakings, was set up in July, 1987 for rendering specialised management and technological services for improving the performance of public sector enterprises in India. However, the company has not been able to make any headway In providing[1] consultancy to public sector enterprises and has therefore not been in a position to contribute in any way towards the efficiency of the concerned public enterprises.

खादी ग्रामोद्योग सेवाकर्मी एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया मांग पत्र

2037. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी आश्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार को खादी ग्रामोद्योग सेवाकर्मी एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उनकी सेवा इस तथ्य के बावजूद श्री गांधी आश्रम (खादी भंडार) से समाप्त कर दी गई कि इस संबंध में उनका प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार को गांधी आश्रमों सहित विभिन्न खादी संस्थानों के कर्मचारियों से इन संस्थानों के प्रबन्ध के ढंग और सेवा शर्तों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने और उपयुक्त उपायों का सुझाव देने हेतु श्री के. सी. सीधिया की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार को खादी ग्रामोद्योग सेवाकर्मी एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री जितेन्द्र नाथ सिंह उर्फ संत जी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि गांधी आश्रमों के कुछ कर्मचारियों और स्वयं उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकार का इन संस्थानों के प्रशासनिक मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है अत: सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।

श्री गांधी आश्रम और खादी की स्वयंसेवी संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याएं

2038. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गांधी आश्रम और खादी की समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं के कर्मचारी अपने वेतनमानों, सेवाशर्तों और अपनी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं और इस [illegible]

में पिछले 4 वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी इन मांगों को रखते आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं के हल के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा शर्तें इत्यादि इन संस्थानों का आंतरिक मामला है और सरकार का इन पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। फिर इन संस्थानों में बहुत बड़ी संख्या में काम कर रहे कर्मचारियों के हित और कल्याण को देखते हुए, सरकार ने 29.6.1990 को श्री के. सी. सोधिया की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करेगी और उपयुक्त उपायों का सुझाव देगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1991 के अन्त में प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

कागज उद्योग के समक्ष कठिनाइयां

2039. श्री ईश दत्त यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वन नीति के कारण उद्योग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कागज उद्योग ने कितने कच्चे माल की मांग की थी ; और

(ग) उन्हें इस अवधि के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में कागज उपलब्ध कराया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) राष्ट्रीय वन नीति के कारण औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनों पर आधारित कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कागज उद्योग को पर्याप्त मात्रा में पारंपरिक कच्चा माल न मिल पाना भी एक समस्या है।

(ख) विभिन्न एककों द्वारा कितना कच्चा माल मांगा जाता है इसके राज्यवार आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जनवरी, से नवम्बर, 1991 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	जनवरी से नवंबर, 1991 तक का उत्पादन (लाख मी० टनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	2.713
2.	असम	1.084
3.	बिहार	0.024
4.	गुजरात	1.670
5.	हरियाणा	1.110
6.	हिमाचल प्रदेश	0.213
7.	जम्मू और कश्मीर	0.009
8.	कर्नाटक	1.196
9.	केरल	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	0.991
11.	महाराष्ट्र	3.515
12.	नागालैंड	0.218
13.	उड़ीसा	1.207
14.	पंजाब	0.820
15.	राजस्थान	0.064
16.	तमिलनाडु	1.616
17.	उत्तर प्रदेश	2.096
18.	पश्चिम बंगाल	0.858
19.	चंडीगढ़	0.016
20.	पांडिचेरी	0.032
	योग :	19.452